



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1980]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 28, 2019/आषाढ़ 7, 1941

No. 1980]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 28, 2019/ASHADHA 7, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2019

का.आ. 2194(अ).—वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, भारत सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बेंगलुरु-I से परामर्श करके, केंद्र सरकार निम्नलिखित न्यायालय को बतौर विशेष न्यायालय नामित करती है, नामतः—

राज्य या संघ राज्य क्षेत्र	धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत विशेष न्यायालय के रूप में नामित सत्र न्यायालय	धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 4 के तहत दण्डनीय अपराध पर विचार हेतु विनिर्दिष्ट क्षेत्र
कर्नाटक	81वां अतिरिक्त नगर सिविल एवं सत्र न्यायालय, (सीसीएच-82), बेंगलुरु	संपूर्ण कर्नाटक राज्य

[फा.सं. सी-18015/14/2018-एडी.ईडी]

विवेक मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th May, 2019

S.O. 2194(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 43 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue and in consultation with the Chief Justice of High Court of Karnataka, Bengaluru-1, the Central Government hereby designates the following court as Special Court, namely:—

State or Union Territory.	Court of Session designated as Special Court under the Prevention of Money-laundering Act, 2002.	Area specified for trial of offence punishable under section 4 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002.
Karnataka.	81 st Additional City Civil and Sessions Court, (CCH-82), Bengaluru.	The entire State of Karnataka.

[F. No. C-18015/14/2018-Ad.ED]

VIVEK MISHRA, Under Secy.